

सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए कार्यशाला में नदारद रहे कई सांसद, गांवों की स्थिति में सुधार के सपने पर प्रश्नचिह्न

कार्यशाला में 56 सांसदों में से 22 सांसद ही पहुंचे

हिन्दुस्तान, दिनांक-21-11-14

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) लांच कर दी गई। लेकिन योजना की शुरुआत होने के मौके पर आयोजित कार्यशाला में ही आधे से अधिक सांसद नदारद रहे। मौका था गुरुवार को केन्द्र और राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आहत उन्मुखीकरण कार्यशाला का।

राज्य के 56 में से सिर्फ 22 सांसद व उनके प्रतिनिधि ही कार्यशाला में उपस्थित थे। आधे से अधिक सांसदों की गैरहाजिरी से राज्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गांवों की स्थिति में सुधार के सपने पर प्रश्नचिह्न लगता दिख रहा है। वहीं अब तक दस सांसदों ने ही अपने आदर्श ग्राम का चयन नहीं किया है।

ये सांसद थे मौजूद : विभाग के तमाम प्रयास के बाद केन्द्रीय राज्यमंत्री और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव,



गुरुवार को होटल पाटलिपुत्र अशोक में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत के लिए आयोजित कार्यशाला में राज्य के कई सांसदों ने भाग लिया। मंच पर उपस्थित सांसद। • हिन्दुस्तान

हरी मांझी, जर्नादन सिंह सीपीआर, वीणा देवी, भोला प्रसाद सिंह, अली अनवर, चौधरी महबूब अली कैसर, मौलाना असरारूल हक कासमी, नित्यानंद राय, सुशील सिंह, अरुण कुमार, छेदी पासवान, संजय जायसवाल, वीरेंद्र चौधरी, सतीश चन्द्र दूबे, कोशलेंद्र

कुमार, अजय निषाद, रामकुमार कुशवाहा, अनिल सहनी उपस्थित थे। सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, आरके सिन्हा आदि के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।
योजना के महत्वपूर्ण पहलू : गांव के

लोगों का व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा व सुशासन। एसएजीवाई का मुख्य उद्देश्य है सांसदों के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गांव की देखरेख व विकास। केन्द्र की 31 स्कीमों का चयन कर उन्हें

राज्य सरकार सहयोग करेगी

ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। सभी जिलाधिकारी व उनकी टीम सांसदों के सभी सुझावों पर अमल करेगी। योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। केन्द्रीय राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने इसके पूर्व योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार का सहयोग मांगा। कहा कि गांवों के विकास से जुड़ी प्रधानमंत्री की यह अद्भुत योजना है।

जिलाधिकारी के माध्यम से जमीनी कार्यान्वयन कराना। प्रारंभ में यह नन फंडिंग योजना रहेगी। लेकिन पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं के साथ मिलाकर उसे सांसदों के नेतृत्व में लागू करना है। वर्ष 2016 तक एक गांव को आदर्श बनाने और 2019 तक दो गांवों

को आदर्श बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2054 तक प्रत्येक वर्ष एक ग्राम को आदर्श बनाते हुए पांच गांवों को पूर्ण विकसित कर आदर्श बनाना है। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक केके पाठक ने योजना की प्रासंगिकता व उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आज से यह योजना बिहार में शुरू कर दी गई है। राज्य के 56 में से 46 सांसदों ने पहले ही आदर्श ग्राम चुन लिया है। मौजूद सांसदों ने कई पूरक सवाल दामे। उन्होंने योजना को लागू करने की दिशा में कई व्यवहारिक कठिनाइयों व अड़चनों की चर्चा की और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में पूछा। श्री पाठक ने सांसदों के बीच पूरी योजना का प्रेजेंटेशन रखा। इनमें दो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीधे वक्तव्य वाले संबोधन भी थे।